



अगर आपको उस इंसान की संगत पसंद है जिसके साथ आप अकेले रह सकते हैं, तो आप कभी अकेले नहीं हो सकते।

-वेन डायर

वर्ष 72 अंक 294 पृष्ठ 12
रीवा, मंगलवार 22 जुलाई, 2025
श्रावण कृष्ण पक्ष 12, विक्रम संवत् 2082
नगर मूल्य 5 रुपए

उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा: स्वास्थ्य को बजह बताया, सत्र के दौरान ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति

नई दिल्ली, जेएनएन। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार रात को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह फैसला उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते लिया है। उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा कि वह 'स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और डॉक्टरों की सलाह का पालन करने' के लिए यह निर्णय ले रहे हैं। उनका इस्तीफा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के तहत तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया गया।

धनखड़ का यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वे संसद के चालू सत्र के बीच पद छोड़ने वाले पहले उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं और उनका अचानक पद छोड़ना संसदीय कार्यों के संचालन पर भी प्रभाव डालेगा। इस्तीफा देते हुए धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक भावुक पत्र लिखा है।

दो साल थे शेष
6 अगस्त 2022 को धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था।



राष्ट्रपति को भेजा पत्र, कहा- चिकित्सा सलाह का पालन करने के लिए त्याग रहे हैं पद

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के प्रति जताया गहरा आभार

राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में धनखड़ ने लिखा, 'स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सलाह के पालन के लिए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र देता हूँ। मैं राष्ट्रपति जी का उनके समर्थन और सौहार्दपूर्ण कार्य संबंधों के लिए गहरा आभार व्यक्त करता हूँ।' उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद को भी सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही सांसदों के स्नेह और विश्वास को अपनी स्मृति में संजोए रखने की बात कही। उन्होंने लिखा, 'मुझे जो अनुभव और सीख उपराष्ट्रपति के रूप में मिली है, वह मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है।'

किसान परिवार से लेकर दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद तक

धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के कठाना गांव में हुआ। एक साधारण किसान परिवार से आने वाले धनखड़ ने राजस्थान विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक और फिर कानून में स्नातक की डिग्री ली। वे सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता रहे और राजस्थान हाई कोर्ट पर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। उनका राजनीतिक करियर 1989 में शुरू हुआ जब वे जनता दल के टिकट पर झुंझुनू से सांसद चुने गए। 1990 में उन्हें केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनाया गया। बाद में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त किए गए।

छह माह के भीतर होगा चुनाव

उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों के वोटों से किया जाता है। संविधान के अनुसार, छह महीने के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है। जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाता, तब तक राज्यसभा की अध्यक्षता वरिष्ठतम सदस्य कर सकते हैं या राष्ट्रपति कोई अंतरिम व्यवस्था कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री का द्वािटी

कार्यकाल मूल्यों और गरिमा का प्रतीक

'धनखड़ जी का कार्यकाल संवैधानिक मूल्यों और गरिमा का प्रतीक रहा। उन्होंने सदन में मर्यादा बनाए रखते हुए उत्कृष्ट नेतृत्व दिया। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ।'

कुछ महीनों से थे बीमार धनखड़ पिछले कुछ महीनों से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। मार्च 2025 में उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था। जून 2025 में उत्तराखंड में एक कार्यक्रम के दौरान भी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। ऐसे में उनके इस्तीफा को चिकित्सकीय सलाह का पालन माना जा रहा है। हालांकि इसके पीछे अन्य राजनीतिक कारणों के भी कयास हैं।

मानसून सत्र: विपक्ष के हंगामे के बाद सरकार संसद में बहस के लिए तैयार ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में होगी 25 घंटे बहस

नई दिल्ली, जेएनएन। संसद के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। सोमवार को विपक्ष ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जमकर विरोध दर्ज कराया। विपक्ष ने पीएम मोदी से इन मुद्दों पर सीधे जवाब की मांग की। बाद में सरकार ने इस पर बहस की घोषणा कर दी है।

सरकार ने घोषणा की है कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में व्यापक चर्चा होगी। लोकसभा में इस पर 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे तक बहस तय की गई है। लेकिन विपक्ष की मांग है कि यह बहस सत्र के प्रारंभ में हो और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी सदन में उपस्थित होकर जवाब दें। विपक्षी दलों का कहना है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है, जिस पर सरकार को ओर से स्पष्टता और पारदर्शिता जरूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भी अब तक आतंकीयों को न पकड़ा गया है, न मारा गया है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी स्वीकार किया है कि इंटे्लिजेंस की विफलता हुई है।



32 दिन चलेगा सत्र

संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक कुल 32 दिनों तक चलेगा। इस दौरान 18 बैठकें होंगी और सरकार की ओर से 15 से अधिक विधेयक पेश किए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13-14 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी। सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले प्रमुख विधेयकों में नया इनकम टैक्स बिल, मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक और नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नंस बिल शामिल हैं।

नए बिल पास और प्रस्तुत

मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा ने बिल ऑफ लैंडिंग बिल, 2025 को पास कर दिया। यह बिल 1856 के भारतीय बिल्स ऑफ लैंडिंग एक्ट की जगह लेगा और समुद्री मार्ग से भेजे गए माल के लिए कानूनी डॉक्यूमेंटेशन का आधुनिकीकरण करेगा। वहीं, लोकसभा में नए इनकम टैक्स बिल पर बनी संसदीय समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। समिति ने इस 622 पन्नों वाले बिल में कुल 285 सुझाव दिए हैं।

महाभियोग प्रस्ताव पर भी किए हस्ताक्षर

सत्र के पहले दिन जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में 145 और राज्यसभा में 63 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। विपक्षी सांसदों ने स्पीकर को ज्ञापन सौंपा। यह प्रस्ताव नकदी बरामदगी को लेकर लाया गया है।

सत्र के बाद: पीएम की बैठक, खड़गे का जन्मदिन

सत्र के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन भी था। इस अवसर पर संसद भवन में कांग्रेस सांसदों ने केक काटा और उन्हें शुभकामनाएं दीं। साथ ही, पीएम मोदी ने संसद भवन में महत्वपूर्ण बैठक की। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता शामिल हुए।

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई कड़ी फटकार राजनीतिक लड़ाई में न हो जांच एजेंसियों का उपयोग

नई दिल्ली, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि राजनीतिक लड़ाइयों का मंच चुनाव होता है, न कि जांच एजेंसियों के दफ्तर। कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को भेजे गए समन को हटाकर ईडी की मंशा पर सवाल उठाए और पूछा कि आखिर एजेंसी का राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल क्यों हो रहा है? मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने यह टिप्पणी मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (मुडा) केस में ईडी की अपील पर

सुनवाई के दौरान की। मुख्य न्यायाधीश ने यहां तक कहा, 'हमारा मुंह मत खुलावाइए, नहीं तो हमें ईडी को लेकर कठोर टिप्पणियां करनी पड़ेंगी।' उन्होंने आगे जोड़ा, 'मेरे पास महाराष्ट्र का नकल फौजदार (राजनीतिक लड़ाई) चुनाव तक लेक है, लेकिन इसके लिए ईडी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल अस्वीकार्य है।' ईडी ने सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मुडा भूमि आवंटन मामले में समन भेजा था। हाईकोर्ट ने यह समन रद्द कर दिया था, जिसे ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।

भोपाल मेट्रो: आरडीएसओ ने परखा ऑसिलेशन और इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस जांच का पहला चरण पूरा, सीएमआरएस टीम की जांच के बाद जल्द शुरू होगी मेट्रो

तेज रफ्तार पर भोपाल मेट्रो आम लोगों के लिए कितनी सुरक्षित है। इसकी जांच करने के लिए लागू मापदंडों के तहत परखा ऑसिलेशन एंड इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस (आरडीएसओ), इंडियन रेलवे की टीम भोपाल पहुंच चुकी थी। टीम ने 9 जुलाई से 21 जुलाई तक सुभाष नगर से एम्स के बीच मेट्रो को विभिन्न गति सीमा और वजन के साथ चलाकर देखा। इस दौरान मुख्य रूप से भोपाल मेट्रो रोलिंग स्टॉक के लिए ऑसिलेशन (दोलन) और इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस की जांच की गई। 15 से 20 दिन बाद कमिश्नर मेट्रो सेपटी के

जागरण संवाददाता, भोपाल। तेज रफ्तार पर भोपाल मेट्रो आम लोगों के लिए कितनी सुरक्षित है। इसकी जांच करने के लिए लागू मापदंडों के तहत परखा ऑसिलेशन एंड इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस (आरडीएसओ), इंडियन रेलवे की टीम भोपाल पहुंच चुकी थी। टीम ने 9 जुलाई से 21 जुलाई तक सुभाष नगर से एम्स के बीच मेट्रो को विभिन्न गति सीमा और वजन के साथ चलाकर देखा। इस दौरान मुख्य रूप से भोपाल मेट्रो रोलिंग स्टॉक के लिए ऑसिलेशन (दोलन) और इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस की जांच की गई। 15 से 20 दिन बाद कमिश्नर मेट्रो सेपटी के

मेट्रो की सुरक्षा जांच करने के लिए भोपाल पहुंची आरडीएसओ की टीम।

भोपाल आने की संभावना है। उनकी ओर से जांच और सुरक्षा मानकों पर रिपोर्ट के बाद मेट्रो संचालन शुरू हो जाएगा। आरडीएसओ के डायरेक्टर

18 माह में होगा नवीन विश्राम गृह का निर्माण विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर व सीएम ने किया भूमिपूजन, अन्य नेता भी रहे मौजूद

विशेष संवाददाता, भोपाल। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बदलते परिवेश में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वे प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। विधायक जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वे अपने दायित्व का ठीक से निर्वहन कर पाएं इसके लिए जरूरी है कि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं एवं सुविधाओं का भी समर्थन पर ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्राणप्रण से जुड़े हुए हैं। तोमर सोमवार को विधानसभा विश्राम गृह में नवीन आवस्य निर्माण कार्य के भूमि-पूजन के उपरांत उपस्थित जनों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नई चुनौतियों को स्वीकार करके प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में औद्योगिक निवेश एवं युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए इनवेस्टर्स से मिल कर वे सात-आठ दिन की विदेश यात्रा करके हाल ही में लौटे हैं। उनकी यह यात्रा सफल होगी एवं प्रदेश, डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में एक औद्योगिक राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल होगा। तोमर ने कहा कि स्वच्छता की दृष्टि से भी प्रदेश लगातार पूरे देश में उत्कृष्ट स्थान बना रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम ने विधायकों के नवीन विश्राम गृह के निर्माण कार्य को प्राथमिकता पर लिया और आज उनके प्रयासों से इसका भूमि पूजन हो रहा है। 18 माह में यह परिसर बन कर तैयार हो जाएगा।



विधानसभा में जल्द ही पूरी तरह पेपरलेस होगा काम, सदस्यों को होगी आसानी

तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश विधानसभा में लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। हमारी विधानसभा जल्द ही ई-विधानसभा में परिवर्तित हो जाएगी और कामकाज पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगा। सदस्यों को जर्मगृह में भी काम करने में इससे आसानी होगी। वर्ष 1958 में इस विधायक विश्राम गृह का निर्माण किया गया था। यहां बने विधायक विश्राम भवन की इमारत बहुत पुरानी हो गई थी। इस भवन ने 67 साल की यात्रा पूरी की है। लेकिन अब सभी विधायकों को यह महसूस हो रहा था कि नया प्रकल्प बनाया जाए क्योंकि इसमें समय के अनुसार सुविधाओं का अभाव है।

औद्योगिक विकास से युवाओं को रोजगार मिलेगा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति एवं विकास हो रहा है। पिछले 11 वर्षों में हमने एसी सफलताएं प्राप्त की हैं कि पूरी दुनिया हमें देख रही है और हमसे जुड़कर काम करना चाहती है। कृषकों के फसल उत्पादन में नवीन तकनीकी के प्रयोग की दिशा में भी हम कार्य कर रहे हैं। औद्योगिक विकास से युवाओं के रोजगार के लिए भी कार्य हो रहा है। सीएम ने बताया कि दुबई और स्पेन यात्रा से मध्य प्रदेश को 11 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हुए प्राप्त हुए हैं। इस अवसर पर संसदीय कार्य एवं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, खेल एवं युवक कल्याण मंत्री विश्वास सारंग, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृष्णा गौर अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण, सदस्यगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मंत्री एवं सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

मांडू में कांग्रेस का दो दिवसीय नव संकल्प शिविर महाराष्ट्र की तरह मप्र में भी की गई 'चुनाव चोरी': राहुल

विशेष संवाददाता, भोपाल। कांग्रेस पुरानी वोटर लिस्ट को डिस्ट्रॉय कर नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र की तरह मध्यप्रदेश में भी चुनाव चोरी किया गया। मैं बिना किसी शक के कह रहा हूँ महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया है। हममें अनेक बार चुनाव आयोग से इलेक्शन डेटा, वोटर लिस्ट, और पोलिंग शिविर को वंचुअल संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विधायकों और पार्टी नेताओं से कहा कि अगर हम सावधान नहीं रहेंगे, हमारी पार्टी तैयारी नहीं करेगी तो जो महाराष्ट्र में हुआ वो एमपी में फिर होगा। हमने महाराष्ट्र चुनाव की वीडियोग्राफी मांगी, तो उन्होंने कानून बदल दिया।

जातिगत जनगणना राहुल गांधी की बड़ी सोच: चौधरी (पेज-02)

